ॐ

विश्व हिन्दू परिषद केन्द्रीय प्रबन्ध समिति बैठक
26–27 जुलाई, 2013
हरियाणा भवन, नारायण नगर, कुमारपाडा, गुवाहाटी (असम)

प्रस्ताव
विषय – अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण

विश्व हिन्दू परिषद की केन्द्रीय प्रबन्ध समिति का यह दृढ़ विश्वास है कि पुण्य नगरी अयोध्या में विराजित भगवान श्रीरामलला का कपडों द्वारा निर्मित मंदिर संतों के साथ–साथ संपूर्ण हिन्दू समाज को व्यथित कर रहा है। जनसमाज यथाशीघ्र भगवान के दर्शन भव्य मंदिर में करना चाहता है। प्रयाग महाकुंभ में संतों के विशाल सम्मेलन के अवसर पर जनसमाज के सामने मार्गदर्शक मण्डल के संतों ने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के तीनों न्यायाधीशों ने एकमत से निर्णय दिया है कि––

1. विवादित स्थल ही भगवान श्रीराम का जन्मस्थान है। जन्मभूमि स्वयं में देवता है और विधिक प्राणी है।
2. विवादित ढांचा किसी हिन्दू धार्मिक स्थल पर बनाया गया था।
3. विवादित ढांचा इस्लाम के नियमों के विरूद्ध बना था, इसलिए वह मस्जिद का रूप नहीं ले सकता।

➲ विद्वान न्यायाधीशों ने मुस्लिमों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस प्रकार यह सिद्ध कर दिया था कि एकमात्र रामलला ही 70 एकड़ भूमिखण्ड के मालिक हैं।

➲ विहिप केन्द्रीय प्रबन्ध समिति यह बताना अपना कर्तव्य समझती है कि केन्द्रीय मार्गदर्शक मण्डल के निर्णय के अनुसार संत–महात्माओं का एक शिष्ट मण्डल महामहिम राष्ट्रपति से भेंट करने गया था। संतों ने राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देते हुए कहा था कि भारत सरकार के अटार्नी जनरल ने 14 सितम्बर, 1994 को सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र देकर कहा था कि––**'यदि यह सिद्ध होता है कि विवादित स्थल पर पहले कभी कोई मन्दिर/हिन्दू उपासना स्थल था तो सरकार की कार्रवाई हिन्दू भावना के अनुसार होगी।'** अतः उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद भारत सरकार की यह बाध्यता है कि वह अपने वचन का पालन करे और भारत सरकार 70 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण हेतु हिन्दू समाज को शीघ्र कानून बनाकर सौंप दे।

➲ विश्व हिन्दू परिषद केन्द्रीय प्रबंध समिति स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि अयोध्या की 84 कोस परिक्रमा की भूमि हिन्दू समाज के लिए पुण्य क्षेत्र है। हिन्दू समाज पुण्य क्षेत्र की ही परिक्रमा करता है, इसलिए इस पुण्य क्षेत्र में हिन्दू समाज किसी भी प्रकार के इस्लामिक प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। यदि वहां कोई इस्लामिक प्रतीक बनाया गया तो वह विदेशी आक्रान्ता बाबर के रूप में जाना जायेगा जिसके कारण हिन्दू–मुस्लिम विवाद हमेशा के लिए बना रहेगा।

➲ केन्द्रीय प्रबन्ध समिति का यह सुविचारित मत है कि न्यायालयों की लम्बी प्रक्रिया से शीघ्र निर्णय नहीं आ सकेगा। हिन्दू समाज रामलला को शीघ्रातिशीघ्र भव्य मंदिर में विराजित देखना चाहता है, इसलिए भारत सरकार से प्रबन्ध समिति आग्रह करती है कि जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर के संबंध में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने अपनी भूमिका निर्वाह की और सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो सका ठीक उसी प्रकार श्रीराम जन्मभूमि के विषय में भी संसद के मानसून सत्र में ही कानून बनाकर अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण की सभी कानूनी बाधाएं दूर की जायें अन्यथा हिन्दू समाज निर्णायक आन्दोलन करने को बाध्य होगा।

प्रस्तोता : राजेन्द्र सिंह पंकज

अनुमोदक.....

ॐ

विश्व हिन्दू परिषद केन्द्रीय प्रबन्ध समिति बैठक

26–27 जुलाई, 2013, हरियाणा भवन, नारायण नगर, कुमारपाडा, गुवाहाटी (असम)

प्रस्ताव

विषय – उत्तराखण्ड दैवीय आपदा

उत्तराखण्ड में 16–17 जून 2013 को हुई अति वृष्टि के कारण श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और हेमकुण्ड साहिब सहित देवभूमि के अनेक क्षेत्रों में महाप्रलय जैसी स्थिति बन गई है। भयंकर वर्षा के अतिरिक्त बादल फटने, ग्लेशियर टूटने एवं भूस्खलन के कारण हजारों आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, विद्यालय, मठ–मंदिर, यात्रा मार्ग ध्वस्त हो गए। लाखों नाली कृषि भूमि भी नदियों के प्रभाव की भेंट चढ़ गई।

देश के कोने–कोने से आए लाखों तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय लोगों के, समूह के समूह भूखे–प्यासे, ठण्ड में ठिठुरते हुए, खुले आसमान के नीचे, वर्षा में भीगते हुए अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों–जंगलों में किस प्रकार इधर–उधर भटक रहे थे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 20 जून तक आपदा में फंसे लोग भगवान के सहारे ही मौत से जूझते रहे। इनमें से अनेक परिवारों के हजारों सदस्य काल के गाल में समा गये। अनेक गांवों के स्थानीय लोगों एवं संस्थाओं ने अपने सीमित साधनों के द्वारा हजारों लोगों को आश्रय और भोजन देकर उनकी जीवन रक्षा की।

सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान लेने के पश्चात ही राज्य सरकार 20 जून से हरकत में आई। फलस्वरूप भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) एवं सेना को बचाव और राहत कार्य की कमान सौंपी गई। जिस संवेदनशीलता, अदम्य साहस और अपने जीवन को जोखिम में डालकर जवानों ने एक लाख से भी अधिक लोगों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया उनके इस पराक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी ही है।

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिले में मैग्नेसाइट व खिड़िया मिट्टी का अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है। इस छोटे से राज्य में छोटी–बड़ी मिलाकर लगभग 558 पनबिजली परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। गंगा सहित पवित्र नदियों पर जगह–जगह बड़ी–बड़ी झीलें और पहाड़ों में लम्बी–लम्बी सुरंगें बनाई जा रही हैं। साथ ही जंगलों को बेरहमी के साथ काटा जा रहा है। जिसके फलस्वरूप संपूर्ण हिमालय खोखला और नंगा हो गया है। विश्व के कई पर्यावरणविदों ने सरकार को अनेक बार सचेत किया है कि हिमालय का पर्यावरण बहुत अधिक दबाव नहीं झेल सकता परन्तु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। राजेन्द्र पचौरी रिपोर्ट को भी सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया। राज्य और केन्द्र सरकार की हठधर्मिता 16–17 जून को हजारों लोगों की मौत और संपूर्ण राज्य की तबाही के रूप में सामने आई।

विश्व हिन्दू परिषद केन्द्रीय प्रबंध समिति उत्तराखण्ड सरकार को सचेत करती है कि मात्र पनबिजली उत्पादन व प्रकृति के निर्दयतापूर्वक दोहन को ही विकास नहीं समझना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकार सभी प्रस्तावित परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर भगवती धारी देवी को उसके मूलस्थान पर पुनः प्रतिष्ठापित करे।

केन्द्रीय प्रबन्ध समिति दो टूक शब्दों में उत्तराखण्ड सरकार को बताना चाहती है कि संपूर्ण देश–विदेश में देवभूमि के रूप में ही उत्तराखण्ड जाना–पहचाना जाता है। चार धाम (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ) राजजात की यात्रा, हेमकुण्ड साहिब, पंचकेदार, पंचप्रयाग, महाकुम्भ क्षेत्र, देवात्मा हिमालय और सप्तपुरी हरिद्वार इसी राज्य में आते हैं। जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण देश–विदेश से हिन्दू तीर्थयात्री आस्था के वशीभूत होकर खिंचे चले आते हैं। 16–17 जून को एक

साथ संपूर्ण राज्य में आई भीषण तबाही किसी दैवीय प्रकोप को ही दर्शाती है। गत वर्षों में राज्य और केन्द्रीय सरकार ने जिस बेरहमी से इस देवभूमि के मौलिक स्वरूप को मिटाने, गंगा को बांधने, धारी देवी मंदिर को हटाने और देवात्मा हिमालय को क्षत–विक्षत कर जो जघन्य अपराध किया है उससे दैवीय शक्तियों का कुपित होना स्वाभाविक है। अतः सरकार को यहां की आस्था व जल–जंगल–जमीन और राज्य के देवभूमि स्वरूप को संरक्षित करते हुए विकास की दिशा निर्धारित करनी चाहिए।

राज्य का बहुत बड़ा भूभाग सीमान्त क्षेत्र है। इस घटना के पश्चात् लोग भयभीत और सहमे हुए हैं। सीमान्त क्षेत्रों से लोग पलायन करने को आतुर हैं। जीवनयापन का संकट भी उनके सामने मुंह बाए खड़ा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सड़कों, पुलों और संचार के माध्यमों को शीघ्रातिशीघ्र दुरस्त कर चारधाम की यात्रा को पुनः प्रारंभ कर राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर लोगों का विश्वास बहाल करे।

विश्व हिन्दू परिषद केन्द्रीय प्रबंध समिति सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक एवं सेवाभावी संस्थाओं का आहवान करती है कि आपदा में पीड़ित लोगों के पुनर्वसन और स्वाबलम्बन में बढ़–चढ़कर हाथ बटाएं और साधु–संत राज्य में धार्मिक अनुष्ठान कर स्थानीय लोगों के विश्वास और मनोबल को बनाए रखने में सहयोग करें।

प्रस्तोता : श्री ईश्वरी प्रसाद, हरिद्वार

अनुमोदक .....

ॐ

विहिप–केन्द्रीय प्रबन्ध समिति बैठक–26–27 जुलाई, 2013
हरियाणा भवन, नारायण नगर, कुमारपाड़ा, गुवाहाटी (असम)

प्रस्ताव
विषय : भारत पर चीन का कसता शिकंजा

विश्व हिन्दू परिषद का यह स्पष्ट अभिमत है कि चीन भारत की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरनाक चुनौती बन गया है। परन्तु दुर्भाग्य है कि देश के कई चिंतकों, सुरक्षा विशेषज्ञों और सैन्य सलाहकारों की चेतावनी और चीन की हरकतों के बावजूद केन्द्र सरकार न केवल इस खतरे की अनदेखी कर रही है अपितु इस दिशा में आपराधिक लापरवाही बरत रही है। पिछले दो महीने में चीनी सेना ने चार बार घुसपैठ की; परन्तु भारत सरकार ने जिस प्रकार इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे चीनी सरकार के इरादे और भारत सरकार की लापरवाही दोनों ही स्पष्ट हो जाते हैं। जब चीनी सेनाएं भारतीय सीमा के 27 कि0मी0 अंदर घुसकर टैण्ट लगा देती हैं तो भारत के प्रधानमंत्री इसको शर्मनाक ढंग से 'स्थानीय समस्या' बताकर भारत की सम्प्रभुता पर हुए इस हमले को बहुत ही हल्के से ले रहे थे। दो महीने के शोर–शराबे के बाद चीनी सेनाएं पीछे तो हटीं परन्तु भारत की सेनाओं को अपनी ही सीमा में स्थित चुमार से बंकर हटाने पड़े। 1962 की पराजय के 51 वर्ष पूरा होने के बाद भी भारत सरकार भारत के सामने उपस्थित इस सबसे बड़े खतरे की अनदेखी कर रही है। लगता है कि वे 1962 की हार से कोई सबक नहीं सीखना चाहते।

1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही चीन ने भारत के 90,000 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया था। उसके बाद से चीन इन क्षेत्रों पर लगातार कब्जा किये जा रहा है। 1962 के बाद तो बिना एक भी गोली चलाये वह अपने एजेण्डे को पूरा कर रहा है। अब भारत का लगभग 43000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में जा चुका है। चीन और पाकिस्तान का अपवित्र गठबंधन इस खतरे को कई गुना बढ़ा रहा है। कुछ दिन पूर्व भारत के रक्षामंत्री के चीन दौरे के मध्य ही चीन–पाकिस्तान ने 200 कि0मी0 लम्बी सुरंग बनाने की अनधिकृत संधि की है। यह सुरंग गुलाम कश्मीर से होकर जायेगी। गुलाम कश्मीर में ही 13000 से अधिक चीनी सैनिक तैनात हैं। उसने वहां पर सैकड़ों मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। म्यानमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने शिकंजे में कसकर भारत को चारों ओर से घेरने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के कोको और श्रीलंका हमटोटा द्वीपों पर चीन अपने सैन्य अड्डे बना चुका है। चीन ने भूटान के उन क्षेत्रों में गतिविधियां प्रारंभ कर दी है जो 'चिकन नैक' के नजदीक है। इससे वह पूर्वोत्तर को शेष भारत से काटने की योजना बना रहा है।

चीन ने तिब्बत को आणविक कचरे का भण्डार बना दिया है जिसके कारण तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र व सतलुज जैसी प्रमुख नदियां खतरनाक रूप से प्रदूषित हो सकती हैं। चीन ने इन दोनों नदियों पर बांध बनाकर इन दोनों महत्वपूर्ण नदियों को एक हथियार के रूप में प्रयोग करने के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वह जब चाहे इनके बहाव को रोककर सूखा ला सकता है और जब चाहे इन क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ की स्थिति निर्माण कर सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी चीन का शिकंजा खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है। भारतीय बाजारों में चीनी उत्पाद इतने अधिक मात्रा में आ चुके हैं जिससे अब कई क्षेत्रों में भारत के कारखानों पर ताले लग चुके हैं। चीनी उत्पादों पर यह निर्भरता और व्यापार असंतुलन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक विनाशकारी संकेत है। भारत में कई आतंकवादी संगठनों को चीन के द्वारा प्रशिक्षण और हथियार देने के कई बार साक्ष्य मिले हैं। पूर्वोत्तर में कई आतंकवादी संगठनों के चीन के साथ सबंध किसी से छिपे नहीं हैं। विश्व हिन्दू परिषद इन सब खतरों के विषय में भारत सरकार को जागरूक करती रही है; परन्तु दुर्भाग्य से भारत के वामपंथी कम्युनिस्ट चीन के इन षडयन्त्रों के लिए भारत सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। शायद वे 1962 के इतिहास को दोहराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उन्होंने चीनी सेनाओं का स्वागत करते हुए भारत को ही हमलावर बताया था।

विश्व हिन्दू परिषद की प्रबन्ध समिति भारत सरकार से यह मांग करती है कि अब उन्हें कुम्भकर्णी निद्रा को त्याग कर चीन के अपवित्र इरादों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। भारत सरकार को यह समझना चाहिए कि उनके इरादे कमजोर हो सकते हैं परन्तु देश कमजोर नहीं है। हमारे देश में चीन की हर चुनौती का जवाब देने की भरपूर क्षमता है। इस चुनौती का जवाब देने के लिए हमारे सुझाव हैं :–

1. भारत सरकार कठोरता पूर्वक चीन को यह बताये कि भारत की सार्वभौम सीमाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
2. 1962 में संसद के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का सम्मान करते हुए भारत सरकार शीघ्र चीन द्वारा हथियाये गये भू–भाग को पुनः वापस लेने का प्रभावी प्रयत्न करे।
3. चीनी वस्तुओं के भारत में आयात रोकने हेतु चीनी वस्तुओं पर कठोर कर एवं सीमा शुल्क लगाये।
4. चीन की सैन्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को नौसेना, वायु सेना व थलसेना का आधुनिकीकरण करना चाहिए।
5. नेपाल व भूटान में भारत समर्थक ताकतों को मजबूत करे तथा चीन समर्थित मावोवादियों का विरोध करे।
6. चीन द्वारा आतंकवादी देश पाकिस्तान एवं इस क्षेत्र में नुकसान देने वाली अन्य ताकतों का समर्थन देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग–थलग एवं बेनकाब करे।
7. चीन सरकार की खतरनाक गतिविधियों के प्रतिकार के लिए सुरक्षा व गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करे।
8. तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नद व सतलुज नदी पर बांध बांधने तथा अन्य हिमालयी नदियों के जल के प्रवाह को मोड़ने से रोके।
9. चीन समर्थक बुद्धिजीवी गुटों के आर्थिक तंत्र की छानबीन करे।
10. पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, म्यानमार, बांग्लादेश और श्रीलंका में चीनी प्रभाव को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करें तथा जापान, वियतनाम, मालदीव जैसे चीनपीड़ित देशों के साथ सम्बन्धों को प्रगाढ़ करें।
11. चीन से बिजली के ठेकों और कम्प्यूटरों के आयात पर पूरी तरह निगरानी रखी जाए।
12. भारत चीन संधि को रद्द किया जाए। सन् 1914 में ब्रिटिश भारत तथा तिब्बत के बीच हुए समझौते में चीन उस समय हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। अतः चीन का तिब्बत पर अधिकार पूर्णतः अनुचित है।

इसके अतिरिक्त विश्व हिन्दू परिषद की केन्द्रीय प्रबन्ध समिति चीन के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले खतरों के प्रतिकार हेतु सभी देश भक्त नागरिकों से आह्वान करती है कि निम्नलिखित कार्य करें :––

01. व्यवसायी तथा आयातकर्ता बन्धु चीन के निम्नस्तरीय वस्तुओं का व्यापार नहीं करें।
02. भारतीय उपभोक्ता चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करे तथा अपनी असीमित क्रय शक्ति का प्रयोग भारतीय उत्पादों को खरीदने में करें। चीन एक भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत के विशाल बाजार में चीनी उत्पादों को रोककर चीन पर आवश्यक दबाव बनाया जा सकता है।

प्रस्तोता :.....

अनुमोदक : विनायकराव देशपाण्डे

Dated : 26-7-2013

ॐ

विश्व हिन्दू परिषद केन्द्रीय प्रबन्ध समिति बैठक
26–27 जुलाई, 2013, हरियाणा भवन,
नारायण नगर, कुमारपाडा, गुवाहाटी (असम)

विषय : असम पर प्रस्ताव

विश्व हिन्दू परिषद की केन्द्रीय प्रबन्ध समिति की भारत सरकार से मांग है कि भारत में प्रवेश करनेवाले उन सभी हिन्दुओं को नागरिकता प्रदान की जाए जो बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरवादियों, सरकारी प्राधिकारियों और अन्य एजेन्सियों द्वारा विभिन्न तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और मजहबी अत्याचारों से पीड़ित वहां से आते हैं।

ऐसे अत्याचारों से पीड़ित हिन्दू वहां अपनी चल–अचल सम्पत्ति छोड़कर लगातार भारत आ रहे हैं। भारत सरकार और असम की राज्य सरकार को भारत में आनेवाले प्रत्येक परिवार को उचित भूखण्ड देकर प्रतिपूर्ति करनी चाहिए।

इसी प्रकार निर्वाचक नामावलियों में संदिग्ध हिन्दू मतदाताओं की संख्या मुसलमान घुसपैठियों से अधिक हो गयी है जिसके कारण गंभीर मानसिक और भौतिक यंत्रणा हो रही है। इसलिए भारत सरकार और असम की राज्य सरकार को निर्वाचक नामावलियों में से 'डी' अक्षर जो उनके नामों के सामने छपा होता है, उसे हटाकर उनके नामों को नियमित करना चाहिए।

असम सरकार से घालमेल करके केन्द्रीय सरकार ने असंवैधानिक तौर पर और जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं के विरुद्ध दूमावाड़ी और लतिटीला में, जो करीमगंज और धुबड़ी जिले में हैं भारत की लगभग 1400 बीघे भूमि बांग्लादेश को देने का निर्णय किया है। विश्व हिन्दू परिषद ने इस मामले पर अत्यन्त गंभीर रूख अपनाया है और बांग्लादेश को यह भूमि सौंपना अवैध और असंवैधानिक है अतः इसका घोर विरोध करने का निश्चय किया है। साथ ही विश्व हिन्दू परिषद यह भी मांग करती है कि भारतीय सीमाओं की सुरक्षा हेतु बार्डर फैसिंग का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाए।

चीन के द्वारा लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारतीय क्षेत्रों में लगातार घुसपैठ हो रही है। भारत सरकार चीन की चुनौती के प्रति बेपरवाह प्रतीत होती है। वस्तुतः यह लाचार है। इतना ही नहीं चीन ने भारत सरकार के इस ढीले–ढाले रवैये को देखते हुए ब्रह्मपुत्र नद (त्रांगफौज) पर चीन और तिब्बत में बड़े–बड़े बांध बना डाले हैं और इस नद के मार्ग को बदल रहा है जिसका असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत पर गंभीर जैव विविधता और आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। युद्ध होने पर चीन भारी मात्रा में ब्रह्मपुत्र का पानी छोड़कर उसका शस्त्र के रूप में प्रयोग करके असम और अरूणाचल प्रदेश में जानमाल की भारी हानि कर सकता है।

यदि चीनी सरकार ब्रह्मपुत्र पर बनाए गए बांधों के संयुक्त निरीक्षण के अनुरोध को नहीं माने तो भारत सरकार को चीन से हो रहे आयात को तत्काल रोक देना चाहिए, क्योंकि इस आयात से भारत के लघु उद्योग नष्ट हो रहे हैं। अतः यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार इन बांधों को रुकवाने, हटवाने के लिए कूटनीतिक और अन्य तरीके से कठोर कदम उठाए।

पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से मिलकर बांग्लादेश के जिहादी हिंसात्मक होकर सक्रिय हो गए हैं और असम और मेघालय के मुस्लिमबहुल क्षेत्रों में इनकी सतत घुसपैठ और प्रभाव चिंताजनक रूप ले रहे हैं। असम और मेघालय में इन बांग्लादेशी मुस्लिम कट्टरवादियों की हिंसात्मक

गतिविधियों के प्रति न्यायतंत्र की चेतावनियों की अनदेखी करते हुए असम, मेघालय की सरकारें और केन्द्र सरकार लापरवाह हैं।

विश्व हिन्दू परिषद का असम, मेघालय और केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भारत भूमि पर इन जेहादियों की घुसपैठ को और उनकी घातक गतिविधियों को रोके। साथ–साथ उत्तर पूर्वी भारत के मूल निवासियों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध करे।

माओवादी छत्तीसगढ और अन्य राज्यों से असम तक एक लाल गलियारा बनाने की दिशा में यत्नशील हैं और इन माओवादियों के चंगुल में अनेक बेरोजगार और शिक्षित युवा फँस गए हैं जिनसे राज्य की शान्ति के भंग होने का गंभीर खतरा है। इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाकर और माओवादी खतरे से निबटने हेतु खुफिया तंत्र को मजबूत करके सुरक्षा एजेन्सियों को सशक्त करे।

विश्व हिन्दू परिषद की पुरानी मांग है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी को सन् 1951 की नागरिकता के आधार पर अद्यतन बनाए, इसे पुनः दोहराया जाता है तथा विहिप की ओर से यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि ''असम पंचायत अधिनियम 1994'' में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा बनेगी। सरकार इस अधिनियम में संशोधित करके प्रत्येक ग्राम सभा को यह शक्ति प्रदान कर सकती है कि वह अपनी जनसंख्या पंजी रखे ताकि गांव में अवैध घुसपैठ को रोका जा सके और संबंधित अधिकारियों को इसकी लिखित रपट भेजा जा सके। इस प्रकार रखी गयी पंजी से जनगणना विभाग और गृह मंत्रालय को जनसंख्या का उचित लेखा–जोखा रखने में सहायता मिलेगी, साथ–साथ बंगलादेशी घुसपैठ का भी पता चलेगा।

असम में माजुलि द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी–द्वीप है जिसपर एक सिविल उपमंडल और चार सबसे बड़े और अत्यन्त प्रसिद्ध सत्र अवस्थित हैं। इन सत्रों के कारण यह द्वीप हिन्दुओं के लिए पवित्र है। हिन्दुओं की इस पावन भूमि में ईसाई दुष्प्रचार और गतिविधि धीरे–धीरे बढ़ रही है और वे माजुलि में चर्च बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईसाई गतिविधि से वैष्णव सम्प्रदाय और संस्कृति के अस्तित्व को गंभीर खतरा है। माजुलि द्वीप को शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नद के द्वारा हो रहे कटाव से भी खतरा है। विश्व हिन्दू परिषद असम की जनता की पुरानी मांगा को पूरा करने का आग्रह करता है कि माजुलि द्वीप को ''विश्व सांस्कृतिक निधि'' घोषित किया जाए और कटाव को रोकने के उपाय किए जाएं। असम के बहुसंख्यक लोग महापुरुषों श्रीमंत शंकर देव, माधवदेव और दामोदर देव द्वारा स्थापित व प्रसारित वैष्णव मत के अनुयायी हैं। इन महापुरुषों ने सम्पूर्ण असम के सत्रों और नामघरों की स्थापना की। ये सत्र हमारे हिन्दू धर्म के मठों के समान हैं, इन महापुरुषों ने इन सत्रों को हजारों बीघा उपजाऊ भूमि दान में दी। इन सत्रों की भूमि को मुसलमानों और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा कब्जा कर लिए जाने का गंभीर खतरा है। इन भू–माफियाओं ने पहले ही 43 सत्रों की 7552 बीघा भूमि हथिया ली है। विहिप की मांग है कि असम सरकार इन भू–माफियाओं को गिरफ्तार करे और इन घुसपैठियों के शिकंजे से इस भूमि को खाली कराए।

उत्तर पूर्वी भारत के लोग अपने पंथ और अपनी स्वाधीनता के घोर प्रेमी हैं, इस आस्था के कारण ही विगत 700 वर्षों में कोई मुस्लिम आक्रमणकारी इस पावन भूमि में घुस नहीं सका। अपने सम्मान की रक्षार्थ इस क्षेत्र का संघर्ष का अपना इतिहास है। विगत की कुछ घटनाओं ने इसे सिद्ध कर दिया है। विहिप की प्रबंध समिति की केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को चेतावनी है कि इन सब समस्याओं का हल निकाले क्योंकि ये सब उत्तर पूर्व के लोगों के सम्मान, प्रतिष्ठा और अस्तित्व से सुसम्बद्ध हैं।

प्रस्तावक – अजित कुमार जाना

अनुमोदक .....

Vishva Hindu Parishad
Governing Council Meeting
Haryana Bhavan, Narayana Nagar, Kumarpara, Guwahati
24 – 28 July 2013

Resolution on Assam

The Governing Council of Vishva Hindu Parishad demands the Central Govt. to confer citizenship to all the Hindus entering Bharat on account of various forms of Social, Economical and religious atrocities committed on them by Muslim fundamentalists, Government authorities and other agencies in Bangladesh. Hindus are On account of such atrocities constantly migrating leaving behind their movable and immovable properties should be duly compensated by the Central Government and the state Government of Assam by allotment of suitable plot and land to each family in Bharat.

Similarly The Hindu D Voters (Doubtful Voters) in the electoral rolls have outnumbered than the Muslim infiltrators, causing serious mental and physical agonies. Therefore it is demanded that the Central Govt. and also the Assam Government should take appropriate steps to regularize the Hindu voters by deleting the letter "D" against their names in the electoral rolls.

The Central Govt. in connivance with the Assam state Government, unconstitutionally and against the wishes and feelings of the people of Assam has decided to transfer about 1400 bighas of Bharat Land in Dumabari and Latitilla sectors of Karimganj and Dhubri Districts to Bangladesh.
Vishva Hindu Parishad takes a serious note of this issue and resolves to strongly oppose this illegal and unconstitutional action of the Central Govt. and Assam Govt. to transfer the land to Bangladesh. Vishwa Hindu Parishad further demands to ensure the protection of borders by means of fencing at Borders as soon as possible.

Chinese have been making continuous intrusion in to the territory of Bharat at various points in Ladhakh, Sikkim and Arunachal Pradesh. Govt. of Bharat appears to be indifference rather helpless in meeting the Chinese challenge. Further China taking advantage of the clay-footed approach of the Government has been resorting to the construction of mega Dams over River Brahmaputra(Trangphoj) at various places in Tibet and China, and even diverting the river course itself, which will have very serious biodiversity and economic effect on Assam and entire north east. In the event of war, China may use water weapon by releasing huge quantity of water which may cause huge loss of human lives and property in Assam and Arunachal Pradesh. In case the Chinese govt. do not respond positively for joint inspection of the dams constructed over Brahmaputra, the Central Govt. should stop all imports from China forthwith as these imports have been instrumental in destroying our small industries.

Therefore it is resolved that the Central Govt. should take strict action through diplomatic and other means against China to stop/remove these Dams.

Since recent past along with Pakistan, the Jihadis in Bangladesh have become violently active and their continued infiltration and influence in the Muslim dominated areas of Assam and Meghalay become discernible. In spite of such violent activities by Bangladeshi Muslim fundamentalists in Assam and Meghalaya and the warnings from judiciary, the govt. of Assam, Meghalay and Central Govt. seemed to be unconcerned.

The Vishva Hindu Parishad urges up on the Governments of Assam, Meghalay and the Central to curb the infiltration of Jihadis and their violent activities on the Bharat soil and also provide adequate security to the indigenous people of Northeast Bharat.

The Maoists have been active in carving out a red-corridor right from Chattisgarh and other states to Assam and many unemployed and educated youths drawn in to the Maoists designs, which has seriously threatening the peace in the state. In such a situation it is urged up on the Central Govt. to strengthen the security agencies by employing adequate number of paramilitary forces and intelligence personnel in dealing the Maoist threat.

The Vishva Hindu Parishad reiterates its demand to immediately up-date the National Register of Citizens (NRC) based on the 1951 register on the lineage basis. At the same time VHP wants to bring to the notice of the people of Assam and the Assam Government that "The Assam Panchayat Act 1994 makes a provision of having "Gram Sabha" in each and every village. The Assam Government can empower the Gram Sabha in each village by bringing about suitable Legislative changes in the act to maintain a "Population Register" of their respective village, so that any illegal infiltration in to the village can be checked and also reported to the concerned authorities of every infiltration in to the village. The population register so maintained by the Gram Sabha can be useful to the department of Census and Ministry of Home Affairs in maintaining proper count of the population and also the illegal infiltration from Bangladesh.

The island of Majuli in Assam is the biggest river island in the world encompassing a civil sub-division and Vaishnavite center with four biggest and most prominent SATRAS. Because of these Satras this island is a sacred place to Hindus. In this sacred land of Hindus, Christian activity and propaganda is gradually increasing and they are trying to establish a Church in Majuli. The Christian activity is a threat to the very existence of Vaishnava religion and culture. Majuli Island is also facing another threat of continuous erosion by the mighty river Brahmaputra. VHP demands the central and the state governments to fulfill the long pending demand of the people of Assam by declaring the Majuli Island as a "world Heritage Center" and to take up all the measures required to stop the erosion.

Majority people of Assam are the followers of Vaishnavism founded, preached, established and propagated by Mahapurush Shrimant Shankar Dev, Shri Madhav Dev and Damodar Dev. These Mahapurushas established Satras and Namghars throughout the length and breadth of Assam. These Satras are like Matts of our Hindu dharma. The followers of These Mahapurushas donated thousands of Bighas of fertile lands to these Satras. At present these Satras are facing a serious threat of grabbing their lands and properties by Muslims and Bangladeshi Muslim infiltrators. About 7552 Bighas land belonging to 43 Satras is already grabbed by these grabbers. VHP demands that the state Government of Assam to arrest these grabbers and vacate the lands from the clutches of these infiltrators.

People of Northeast love their religion and freedom from the core of their hearts. It is due to this great zeal that no Muslim invader could enter this sacred land for 700 years. This region has a great history of struggles to save their honor. Certain incidents of recent past have proved it. The Governing council of VHP warns the Central and State governments to resolve all these issues which are very well related to the glory, prestige and existence of the people of Northeast.

Proposed by: Ajit Kumar Jana, North East Zonal Secretary

Seconded by:----------